1	2	3	4
3. सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज, पुणे	138	10 सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार जो, चयन की अन्य शर्तों को पूरा करते हैं, के लिए आरक्षित हैं । मेडिकल कालेजों वाले राज्यों द्वारा एवं जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली सहित कुछ अन्य चिकित्सा संस्थाओं द्वारा भारत सरकार को केन्द्रीय पूल के लिए दी गई नियत सीटें बिना मेडिकल कालेज वाले राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों, मेडिकल कालेज, रक्षा कार्मिकों के बच्चों अन्य अर्ध सैनिक संगठन, सांस्कृतिक विनिमय अध्येता वृत्ति से पुरस्कृत विदेशी छात्रों, स्वयं वित्त-पोषित विदेशी छात्रों, बर्मा, श्रीलंका से आए शरणार्थियों आदि को आबंटित की जाती हैं । इन सीटों का आबंटन वर्ष दर वर्ष भिन्न-भिन्न होता है जो केन्द्रीय पूल में एम०बी०बी०एस० सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है । छात्रों का चयन एवं नामांकन से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ संबंधित मंत्रालयों द्वारा जिन्हें सीटें आबंटित की जाती हैं, किया जाता है ।	

People living below poverty line in Orissa

1732. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of PLANNING be pleased to refer to answer to Unstarred Question 3066 given in the Rajya Sabha on the 28th March, 1989 and state:

(a) what are the schemes being formulated for raising above the poverty line the condition of persons in Orissa; and

(b) the number of persons proposed to be brought above the poverty line during the current financial year?

THE MINISTER OF PLANNING AND THE MINISTER OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI MADHAVSINH SOLANKI): (a) The two major national anti-poverty programmes being implemented in Orissa during the current year are:

(i) Integrated Rural Development Programme (IRDP) and

(ii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY). National Rural Employment Programme (NREP) and Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP) have been merged with the Jawahar Rozgar Yojana. In addition, in the State Plan there is an anti-poverty programme called the Economic Rehabilitation of Rural Poor,

(b) No yearwise target for persons crossing the poverty line is fixed. However, during the current financial year it is proposed to assist 1.4 lakhs families under IRDP in Orissa. Similarly, under Jawahar Rozgar Yojana it is proposed to create 467.78 lakh mandays of employment.